RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 209
दि. 03.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मतगणना पर कड़ी नजर: बंगाल चुनाव में पारदर्शिता के लिए आयोग की सख्त तैयारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पूरे देश की नजरें एक बार फिर इस अहम प्रक्रिया पर टिक गई हैं, जहां नतीजे केवल सत्ता का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता की भी परीक्षा लेंगे। इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए Election Commission of India ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं, ताकि मतगणना पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला लिया है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर चरण नियमों के तहत ही पूरा हो।

आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह तैनाती विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में की गई है जहां एक से अधिक मतगणना हॉल बनाए गए हैं। ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। मतगणना पर्यवेक्षक सीधे आयोग के निर्देशों के तहत काम करेंगे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे, जबकि पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना केंद्रों के बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना हॉल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।

इस बार आयोग ने तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया है। मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए ईसीआईनेट प्रणाली के तहत क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। इससे अनधिकृत लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी। सुरक्षा के इन उपायों का उद्देश्य केवल नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि यह विश्वास दिलाना भी है कि हर वोट की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। इसके साथ ही मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अधिकृत अधिकारी—जैसे मतगणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी—ही फोन अपने साथ रख सकेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी लीक होने या प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना को खत्म किया जा सके।

मतगणना के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 17सी-II के माध्यम से कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणामों को एजेंटों की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा। यह फॉर्म संबंधित एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमाण मौजूद रहे। इसके अलावा माइक्रो-पर्यवेक्षक प्रत्येक टेबल पर स्वतंत्र रूप से आंकड़ों का क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि किसी भी त्रुटि की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। यह बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था चुनाव आयोग की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। All India Trinamool Congress ने मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तैनाती को लेकर आपत्ति जताई थी। पार्टी का तर्क था कि केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार का प्रभाव हो सकता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होने का खतरा है। इस मुद्दे को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन Supreme Court of India ने स्पष्ट कर दिया कि मतगणना स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके निर्णयों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

इससे पहले Calcutta High Court ने भी टीएमसी की अपील को खारिज करते हुए यही रुख अपनाया था। अदालत ने कहा था कि मतगणना प्रक्रिया में कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी तरह से चुनाव आयोग का अधिकार है और इसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आयोग अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही मतगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह विवाद उस सर्कुलर से शुरू हुआ था, जिसे आयोग ने 13 अप्रैल को जारी किया था। इस सर्कुलर के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि हर मतगणना टेबल पर कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) से जुड़ा होना चाहिए। आयोग का मानना है कि इससे निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर आशंका जताई थी। हालांकि, न्यायपालिका के फैसलों ने आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराते हुए उसकी स्वायत्तता को मजबूत किया है।

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ है, और अब 4 मई को आने वाले परिणामों का इंतजार है। इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल राज्य की राजनीति को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देने वाला है। ऐसे में मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

चुनाव आयोग की इन तैयारियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संस्था ने इस बार किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की तैनाती, सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, तकनीकी उपाय और बहुस्तरीय निगरानी—all मिलकर यह संकेत देते हैं कि आयोग इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता के साथ ले रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ—जनमत—की रक्षा का दायित्व है।

अंततः, बंगाल चुनाव की मतगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि विश्वास की कसौटी भी है। जिस तरह से आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि परिणाम न केवल सटीक होंगे, बल्कि हर पक्ष के लिए स्वीकार्य भी होंगे। अब नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब मतगणना के साथ-साथ यह भी तय होगा कि इन तैयारियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व को कितना मजबूत बनाया है।

संकट के बीच राहत: 2922 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी, सरकार की सतर्कता से टला बड़ा खतरा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा राहत अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब तक 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की तत्परता और समन्वय क्षमता का प्रमाण है। बीते 24 घंटों में ही 30 नाविकों की सुरक्षित वापसी ने इस अभियान को और मजबूती दी है। राहत की बात यह भी है कि इस दौरान किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमले की कोई घटना सामने नहीं आई, जिससे स्थिति पर नियंत्रण और सतर्क निगरानी का संकेत मिलता है।

यह पूरा अभियान कई मंत्रालयों और एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। Ministry of External Affairs India और Ministry of Ports Shipping and Waterways मिलकर भारतीय मिशनों के माध्यम से लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विदेशी भूमि पर फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है, जिसे सरकार ने गंभीरता से निभाया है। इस संकट के दौरान डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम की भूमिका बेहद अहम रही है। चौबीसों घंटे सक्रिय यह नियंत्रण कक्ष जरूरतमंदों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ है। अब तक इस कंट्रोल रूम ने 8,335 कॉल और 17,838 से अधिक ईमेल का जवाब देकर लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की है। पिछले 24 घंटों में ही 67 कॉल और 144 ईमेल प्राप्त हुए, जिनका त्वरित समाधान किया गया। यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि संकट के समय में सूचना और सहायता का तंत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, और सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से संचालित किया है।

जहां एक ओर युद्ध की आशंका और अस्थिरता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, वहीं भारत के बंदरगाहों पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। माल की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा या भीड़भाड़ नहीं देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था मजबूत और लचीली है। यह स्थिति न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संकट के समय में भी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रह सकती हैं।

हवाई मार्ग की बात करें तो पश्चिम एशिया में धीरे-धीरे उड़ान सेवाएं बहाल हो रही हैं। United Arab Emirates, Saudi Arabia और Oman से भारत के लिए सीमित लेकिन नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं, जिससे लोगों की वापसी में सहूलियत मिल रही है। इसके अलावा Iraq का हवाई क्षेत्र भी सीमित रूप से खुला है, जिसका उपयोग आपातकालीन निकासी के लिए किया जा रहा है।

विशेष रूप से Iran के मामले में स्थिति अधिक संवेदनशील रही है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक 2,490 भारतीय नागरिकों को भूमि मार्गों के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में परिवहन और सुरक्षा दोनों ही बड़ी चुनौतियां होती हैं। इसके बावजूद भारतीय मिशन ने स्थानीय प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया।

सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त सलाह भी जारी की है। यह कदम केवल सतर्कता नहीं, बल्कि संभावित जोखिमों को टालने की रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय लगातार क्षेत्र के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और स्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी कर रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वैश्विक संकट के समय में कूटनीतिक नेटवर्क, तकनीकी संसाधन और प्रशासनिक दक्षता कितनी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय सरकार ने जिस तेजी और संवेदनशीलता के साथ इस स्थिति को संभाला है, वह न केवल देश के भीतर विश्वास पैदा करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को मजबूत करता है।

अंततः, 2922 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए राहत और सुकून की कहानी है। यह उस भरोसे का प्रतीक है, जो हर भारतीय अपने देश से रखता है कि संकट के समय वह अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्षेत्र में हालात किस दिशा में जाते हैं, और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है।

नक्सल चुनौती फिर उभरी: कांकेर में आईईडी विस्फोट, डीआरजी के जवान घायल

कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा हालात एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जब कांकेर जिले के घने जंगलों में आईईडी विस्फोट की घटना ने सुरक्षा बलों को नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। शनिवार को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में हुए इस धमाके में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के तीन जवान घायल हो गए। यह इलाका Kanker district और Narayanpur district की सीमा से सटा हुआ है, जहां लंबे समय से नक्सली गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। घटना उस समय हुई जब डीआरजी की एक टीम जंगल में डिमाइनिंग ऑपरेशन चला रही थी। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को ढूंढकर निष्क्रिय करना था। बताया गया कि जवान इलाके में सावधानीपूर्वक सर्च कर रहे थे, तभी उनका संपर्क एक छिपे हुए विस्फोटक से हुआ, जिससे जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना अचानक था कि तीन जवान इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन साथी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल जवानों को पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार, सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, जिससे राहत की खबर सामने आई है। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि जंगलों में छिपे विस्फोटक अब भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक Sundarraj Pattilingam ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडरों से मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों ने बस्तर क्षेत्र के

कई जिलों में सैकड़ों आईईडी बरामद कर उन्हें निष्क्रिय किया है। यह अभियान लगातार जारी है, लेकिन जंगलों में पहले से बिछाए गए विस्फोटकों की संख्या और उनका फैलाव इस प्रक्रिया को बेहद जोखिम भरा बना देता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांकेर की इस घटना में भी सुरक्षा बल उसी प्रक्रिया के तहत आईईडी को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश विस्फोट हो गया। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित करने का दावा किया था। ऐसे में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और जमीनी हालात को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि नक्सलियों की सक्रियता में काफी कमी आई है, लेकिन उनके द्वारा पहले से लगाए गए विस्फोटक अभी भी खतरा बने हुए हैं और इन्हें पूरी तरह खत्म करने में समय लगेगा। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां जंगल में तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी अन्य संभावित आईईडी को खोजकर निष्क्रिय किया जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बस्तर जैसे क्षेत्रों में नक्सल समस्या केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक चुनौती है, जिसमें विकास, विश्वास और सुरक्षा तीनों का संतुलन जरूरी होता है। आईईडी जैसे हथियार नक्सलियों के लिए एक प्रमुख रणनीति रहे हैं, जो सुरक्षा बलों की गतिविधियों को बाधित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में डिमाइनिंग ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ जोखिम भरे भी होते हैं। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि भले ही नक्सल गतिविधियों में कमी आई हो, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों की सतर्कता, तकनीकी सहायता और खुफिया जानकारी के आधार पर ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

मासूमियत पर वार: पुणे की दर्दनाक घटना ने झकझोरा देश, आरोपी को फांसी दिलाने की तैयारी

पुणे/मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले की भोर तहसील में एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी निर्मम हत्या ने पूरे राज्य ही नहीं, बल्कि देश को भीतर तक हिला दिया है। इस जघन्य अपराध ने एक बार फिर समाज, कानून व्यवस्था और मानवता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने शनिवार को इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएगी।

यह घटना इतनी भयावह है कि इसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। जानकारी के अनुसार, चार साल की मासूम बच्ची अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। शुक्रवार दोपहर वह अचानक लापता हो गई, जिससे परिजनों में घबराहट फैल गई। परिवार ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबले बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के पास स्थित एक तबेले में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की और फिर पकड़े जाने के डर से पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

जब बच्ची लंबे समय तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से खोजबीन तेज की। आखिरकार तबेले से बच्ची का खून से सना शव बरामद हुआ। इस दृश्य ने पूरे इलाके में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाके के

सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें आरोपी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ले जाता हुआ साफ दिखाई दिया। इस अहम सबूत के आधार पर पुलिस ने बिना देर किए आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की।

घटना के बाद राज्य सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता पर एक गहरा कलंक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करेगा, जिससे समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि इस तरह के अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। वहीं सांसद Supriya Sule ने भी इस घटना को मानवता पर धब्बा करार देते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय की मांग की। शिवसेना की प्रवक्ता Shaina NC ने भी इस मामले को समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि कानून का डर खत्म होता जा रहा है, जिसे फिर से स्थापित करना बेहद जरूरी है।

यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक आईना है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी व्यवस्था में ऐसी दरारें क्यों हैं, जिनसे होकर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। एक ओर जहां कानून सख्त होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति यह संकेत देती है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता की भी उतनी ही जरूरत है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिलती है, बल्कि समाज में एक सख्त संदेश भी जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और मजबूत हो, ताकि अदालत में कोई भी तकनीकी कमी आरोपी को बचने का मौका न दे सके।

इसके साथ ही, यह घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। समाज में जागरूकता बढ़ाने, बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। परिवार, स्कूल और समाज—तीनों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

अंततः, पुणे की यह घटना केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—एक ऐसी चेतावनी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अभी नहीं जागे, तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज की आत्मा को बार-बार झकझोरती रहेंगी। सरकार की सख्ती, न्यायपालिका की तेजी और समाज की जागरूकता—इन तीनों का संतुलन ही इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा सकता है। फिलहाल, पूरा देश उस मासूम के लिए न्याय की मांग कर रहा है, जिसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई, और उम्मीद कर रहा है कि दोषी को ऐसी सजा मिले, जो भविष्य के लिए एक मजबूत उदाहरण बने।

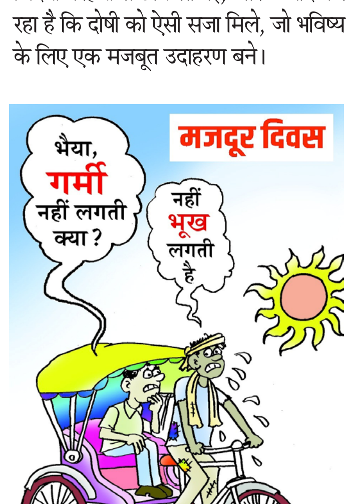

संपादकीय

ध्वनि प्रदूषण का सेहत पर घातक असर

यूं तो हाल के वर्षों में आम भारतीय की अभिव्यक्ति में तल्खी व शोर का ग्राफ तेज हुआ है। अभिव्यक्ति का मुखर होना अच्छा है लेकिन उसका तल्ख होना, किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे हमारे परिवेश में लगातार बढ़ता शोर झेलना हमारी नियति हो चला है। सड़कों पर वाहनों के शोर, नये दौर के कर्कश संगीत से लेकर राजनीतिक विमर्श में होने वाले शोरगुल वाले संवाद से लेकर तमाम ऐसा कुछ घट रहा है, जो हमारी परेशानी का सबब बन रहा है। यूं तो कोई प्रमाणिक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक शोध व्यापक रूप में हमारे सामने तो नहीं आए हैं जो ठीक-ठीक बताएं कि ध्वनि प्रदूषण हमारी सेहत पर कितना घातक असर डाल रहा है। लेकिन गाहे-बगाहे सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि लगातार बढ़ता शोर हमारी सेहत बिगाड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए उचित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और दंड के प्रावधान लागू होते नजर नहीं आते हैं। लेकिन विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष बता रहे हैं देश के महानगरों से लेकर कस्बों तक हमारे परिवेश का शोर तय मानकों से कहीं अधिक है। जाहिरा तौर ये शोर हमारी सेहत को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। जिससे न केवल हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है बल्कि नींद में कमी, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप के अलावा हृदय रोग तक का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस दिशा में कागजों में तो लुभावनी योजनाएं तो बनायी जाती हैं लेकिन जमीनी हकीकत बदलती नजर नहीं आती। यह सुखद है कि पिछले दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस दिशा में नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ की है। दावा किया जा रहा है कि प्रदूषण के स्रोतों की कायदे से निगरानी होगी। इसके अलावा समयबद्ध ढंग से कार्रवाई होगी। साथ ही जुर्माना भी अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अच्छी योजना कितनी जमीनी हकीकत बनती है।

लेकिन सवाल यह है कि जब देश में पहले से शोर नियंत्रण के कानून मौजूद हैं और हमारी अदालतें भी समय-समय पर हमारे नीति नियंताओं को आगाह करती ही रहती हैं, तो फिर सूरत क्यों नहीं बदलती। आखिर इन नियम-कानूनों के क्रियान्वयन में कहां खोट रह जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, 2000 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों, निर्माण कार्यों और उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, वाहनों के हार्न आदि अन्य स्रोतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो पाए। उल्लेखनीय है कि ये प्रावधान दिन व रात के लिये अलग-अलग हैं। जिसके अंतर्गत रात के दस बजे से लेकर सुबह छह बजे के मध्य लाउडस्पीकर लगाना मना है। यदि अपरिहार्य कारणों से कुछ अधिक समय के लिये इसका उपयोग किया भी जाना है तो संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों का जमकर उल्लंघन करना शान समझा जाता है। जाहिर बात है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी इसकी निगरानी और रोकने के लिये होती है वे अपने दायित्वों को भलीभांति निर्वहन नहीं करते हैं। सख्ती के अभाव में लोग इसे न्यू नॉर्मल बना देते हैं। विडंबना यह है कि छोटे शहरों व कस्बों ही नहीं, बड़े शहरों में भी ध्वनि का स्तर नापने वाले यंत्र या तो लगे नहीं हैं, या फिर वे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। यही वजह है कि देश के सामने वह तस्वीर नहीं उभरती कि देश में ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना घातक हो चला है। जाहिर बात है कि देश में जब प्रामाणिक डाटा ही उपलब्ध नहीं है तो उसके निदान और उसके पड़ने वाले घातक प्रभावों की हकीकत कैसे सामने आएगी। वास्तव में गैर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यदि वे फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

Mythos AI चमत्कारी भी है और विनाशकारी भी, इसके प्रभावों को लेकर दुनियाभर की सरकारों की नींद उड़ गई है

> ब्रिटेन के एआई सुरक्षा संस्थान ने भी मिथोस का परीक्षण किया है और इसे पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक सक्षम और खतरनाक बताया है। यह मॉडल कई चरणों वाले साइबर हमलों का अनुकरण करने में सफल रहा है और बिना मानवीय निर्देश के कमजोरियों की पहचान कर सकता है।

एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के बीच एक नया मॉडल वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। यह है एन्थ्रोपिक द्वारा विकसित मॉडल मिथोस। यह उन्नत प्रणाली जहां साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, वहीं इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर सरकारों, बैंकों और विशेषज्ञों के बीच गंभीर आशंकाएं भी उभर रही हैं। हम आपको बता दें कि मिथोस एक ऐसा एआई मॉडल है जो कंप्यूटर प्रणालियों में मौजूद छिपी कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में सक्षम बताया गया है। कंपनी के अनुसार यह उन त्रुटियों को भी खोज सकता है जिनके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को खुद जानकारी नहीं होती। इन्हें जीरो डे कमजोरियां कहा जाता है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद सुधार का समय नहीं मिल पाता। मिथोस की यही क्षमता इसे अत्यंत शक्तिशाली और साथ ही खतरनाक बनाती है। कंपनी ने सात अप्रैल को इस मॉडल के अस्तित्व की घोषणा की थी, लेकिन इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी करने से साफ इंकार कर दिया। कारण स्पष्ट है कि यदि यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो वैश्विक साइबर सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि, सीमित रूप से कुछ कंपनियों और बैंकों को इसके परीक्षण की अनुमति दी गई है ताकि वह इसके जोखिमों को समझ सकें।

हाल ही में स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह सामने आया कि कुछ अनधिकृत लोगों ने इस मॉडल तक पहुंच हासिल कर ली थी। यह घटना इस बात का संकेत है कि इतने संवेदनशील उपकरण को पूरी तरह नियंत्रित रखना कितना कठिन है। इससे तकनीकी कंपनियों की क्षमता पर भी सवाल उठे हैं कि वह अपने सबसे जोखिमपूर्ण उत्पादों को कितनी सुरक्षित रख सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मिथोस केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एआई की तेजी से बढ़ती शक्ति का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में जिस गति से प्रगति हुई है, उससे यह आशंका भी बढ़ी है कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही ऐसे मॉडल विकसित कर सकती हैं। इससे साइबर हमलों और बचाव के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है।

ब्रिटेन के एआई सुरक्षा संस्थान ने भी मिथोस का परीक्षण किया है और इसे पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक सक्षम और खतरनाक बताया है। यह मॉडल कई चरणों वाले साइबर हमलों का अनुकरण करने में सफल रहा है और बिना मानवीय निर्देश के कमजोरियों की पहचान कर सकता है। हालांकि, यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह अत्यधिक सुरक्षित प्रणालियों पर कितना प्रभावी होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉडल को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, उसमें कुछ हद तक अतिशयोक्ति भी शामिल हो सकती है। उनका कहना है कि कई सस्ते मॉडल भी कुछ कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम हैं। इसके अलावा अधिकांश साइबर हमले अब भी साधारण कमजोरियों जैसे कमजोर पासवर्ड या पुराने सॉफ्टवेयर के कारण होते हैं।

फिर भी, मिथोस के संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। यदि इस तरह की तकनीक का दुरुपयोग हुआ तो भुगतान प्रणाली ठप हो सकती है, लोगों के वेतन और लेनदेन रुक सकते हैं, और व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसी कारण अमेरिका में भी इस मॉडल को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा हो रही है। वहां की सरकार ने इसके उपयोग और पहुंच को लेकर सख्त रुख अपनाया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जा रहा है। प्रारंभिक योजना के तहत सीमित संस्थाओं को ही इसकी पहुंच दी गई है और इसके विस्तार को लेकर भी सावधानी बरती जा रही है।

भारत में भी इस मुद्दे ने तेजी से ध्यान आकर्षित किया है। देश को इस मॉडल के शुरुआती परीक्षण से बाहर रखा गया, जिससे नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ गई। सरकार अब अमेरिका और कंपनी के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारतीय कंपनियों को भी इस तकनीक तक उचित पहुंच मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा है कि यह साइबर चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बैंकों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। उद्देश्य यह है कि देश के महत्वपूर्ण ढांचे जैसे बैंकिंग नेटवर्क, दूरसंचार और बिजली प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके।

भारत की चिंता केवल पहुंच तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के जोखिमों को लेकर भी है। यदि अन्य कंपनियां भी इसी तरह के मॉडल विकसित करती हैं और उनका वितरण असमान रहता है, तो कुछ देशों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि भारत समान अवसर और संतुलित नीति की मांग कर रहा है।

इसके साथ ही, देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। उन्हें संवेदनशील प्रणालियों की जांच करने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीक दोधारी तलवार की तरह है, इसका उपयोग सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है और हमलों के लिए भी।

बहरहाल, मिथोस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल सुविधा का साधन नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दुनिया इस नई तकनीकी शक्ति के साथ संतुलन कैसे बनाती है ताकि इसका लाभ भी मिले और जोखिम भी नियंत्रित रहें।

प्रेरणा

जब ज्ञान बनता है जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश

एक शांत शैक्षणिक वातावरण में, जहां विचारों का आदान-प्रदान केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचता है, वहां एक छोटी सी घटना कभी-कभी जीवन का बड़ा सत्य उजागर कर देती है। ऐसा ही एक प्रसंग जुड़ा है Sarvepalli Radhakrishnan से, जो केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि विचारों के ऐसे साधक थे जिन्होंने शिक्षा को जीवन की गहराइयों से जोड़ा। एक दिन वे विश्वविद्यालय में अपने छात्रों को दर्शनशास्त्र का पाठ पढ़ा रहे थे। विषय गंभीर था, और छात्रों के मन में कई जिज्ञासाएं उठ रही थीं। तभी एक छात्र ने साहस करके एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जो अक्सर हर युवा के मन में कहीं न कहीं उठता है—"सर, दर्शन पढ़ने से जीवन में क्या बदलेगा? इससे पेट तो नहीं भरता।" यह प्रश्न सुनते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि आधुनिक सोच का प्रतिबिंब था, जहां शिक्षा को अक्सर केवल रोजगार और आय के संदर्भ में देखा जाता है। सभी छात्रों की नजरें राधाकृष्णन पर टिक गईं। उन्होंने कुछ क्षणों तक मौन रहकर प्रश्न की गंभीरता को आत्मसात किया और फिर शांत स्वर में कहा—"तुम सही कह रहे हो, ज्ञान पेट नहीं भरता।" यह उत्तर सुनकर छात्र के चेहरे पर हल्की संतुष्टि झलकी, मानो उसकी सोच को मान्यता मिल गई हो। लेकिन यह केवल उत्तर का प्रारंभ था।

राधाकृष्णन ने आगे कहा—"लेकिन पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, और सही काम चुनने के लिए विवेक चाहिए। दर्शन वही विवेक प्रदान करता है।" यह वाक्य सरल था, लेकिन उसके भीतर गहरी जीवन दृष्टि छिपी थी। उन्होंने मेज पर रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा—"यह दीपक भोजन नहीं बनाता, लेकिन बिना इसके रसोई अंधेरे में डूबी रहती है। उसी प्रकार ज्ञान जीवन का भार नहीं उठाता, पर वह हमें सही दिशा जरूर दिखाता है।" यह उदाहरण इतना सजीव था कि हर छात्र के मन में उतर गया।

हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां सफलता को अक्सर धन, पद और प्रतिष्ठा से मापा जाता है। शिक्षा को भी उसी नजरिए से देखा जाता है—एक साधन के रूप में, जो हमें आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नजरअंदाज कर देते हैं। शिक्षा केवल जीविका का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को समझने का उपकरण है।

विवेक, जिसका उल्लेख राधाकृष्णन ने किया, वास्तव में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह वह आंतरिक प्रकाश है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देता है। यह केवल नैतिक निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति के पास विवेक होता है, तब वह केवल परिस्थितियों का पालन नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर अपने अनुसार ढालता है।

आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट और तकनीक ने ज्ञान को सुलभ बना दिया है। लेकिन जानकारी और समझ के बीच एक बड़ा अंतर होता है। जानकारी हमें तथ्यों से परिचित कराती है, जबकि समझ हमें उन तथ्यों का अर्थ सिखाती है। यही वह जगह है, जहां दर्शन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दर्शन हमें सोचने की कला सिखाता है, प्रश्न करने की प्रेरणा देता है, और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मार्ग दिखाता है।

राधाकृष्णन का यह संदेश केवल एक छात्र के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष से भी जुड़ी होती है। जब हमारे पास विवेक होता है, तब हम अपने निर्णयों के परिणामों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और जीवन में स्थिरता बनाए रखते हैं।

इस प्रसंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें विनम्रता का महत्व भी सिखाता है। छात्र ने प्रश्न पूछा, और शिक्षक ने उसे न केवल उत्तर दिया, बल्कि उसके दृष्टिकोण को भी विस्तृत किया। यह शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है—जहां संवाद के माध्यम से समझ विकसित होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रश्न करना गलत नहीं है, बल्कि सही उत्तर की खोज का पहला कदम है।

जब हम अपने जीवन में ज्ञान को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। हम केवल परिणामों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि प्रक्रिया को भी महत्व देने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। उस छात्र के लिए वह दिन एक मोड़ साबित हुआ। उसने केवल एक उत्तर नहीं पाया, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया पाया। उसकी आंखों का झुकना केवल लज्जा का संकेत नहीं था, बल्कि यह उस समझ का प्रतीक था, जो उसके भीतर जन्म ले चुकी थी। उसने यह महसूस किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है।

जब हमारे भीतर विवेक का दीपक जलता है, तब हम अंधकार से नहीं डरते। हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यही वह सोच है, जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसकी उपयोगिता में नहीं, बल्कि उसकी दिशा देने की क्षमता में है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अस्तित्व का नाम नहीं, बल्कि उद्देश्य का नाम है। जब हम इस उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब हमारा हर कदम हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। ज्ञान का दीपक भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी रोशनी इतनी व्यापक होती है कि वह पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। यही वह प्रकाश है, जो हमें केवल जीने की कला नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने की समझ भी प्रदान करता है।

Suvendu Adhikari को Giant Killer और भूमिपुत्र के रूप में देखती है जनता, Bengal में BJP को अपने पैरों पर खड़ा करके दिखा दिया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स के अनुमानों ने राज्य की राजनीति को अत्यंत रोचक बना दिया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत प्राप्त हो सकता है। इस राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर उनकी उपस्थिति ने चुनाव को अत्यधिक हाई प्रोफाइल बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी का नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रभावशाली और जमीनी नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर जिले के करकुली में हुआ था। वह वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिसिर कुमार अधिकारी के पुत्र हैं। बचपन से ही राजनीतिक माहौल में पले बढ़े शुभेंदु ने ग्रामीण राजनीति की बारीकियों को नजदीक से समझा, जिससे उनकी छवि एक भूमिपुत्र नेता के रूप में मजबूत हुई।

उनकी शिक्षा भी उनके व्यक्तित्व को संतुलित बनाती है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांथी हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रभात कुमार कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कोलकाता स्थित रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से कला में परास्नातक किया। साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय से भी अध्ययन किया।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1995 में कांग्रेस के साथ की, जब वह कांथी नगरपालिका के पार्षद चुने गए। वर्ष 2006 में वह पहली बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन उनकी असली पहचान नंदीग्राम आंदोलन के दौरान बनी, जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने राज्य की राजनीति को बदल दिया और ममता बनर्जी के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में वह तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार बने और तमलुक से दो बार सांसद भी चुने गए। वर्ष 2016 से 2020 तक उन्होंने राज्य सरकार में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले।

दिसंबर 2020 में उन्होंने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को 1956 मतों से हराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया और वह भाजपा का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। 2026 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लडा, जहां उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है। एग्जिट पोल के अनुसार वह भवानीपुर में भी जीत दर्ज कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है और भाजपा को बहुमत मिलता है, तो शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।

शुभेंदु अधिकारी की आर्थिक स्थिति भी अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण है। 2026 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 85.87 लाख रुपये है। इसमें चल संपत्ति लगभग 20.72 लाख रुपये और अचल संपत्ति लगभग 65.15 लाख रुपये है। उनकी आय का मुख्य स्रोत पारिवारिक संपत्ति है और उन पर कोई देनदारी नहीं है।

हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से जंगलमहल और मेदिनीपुर क्षेत्र में बेहद मजबूत है। इन क्षेत्रों में उनकी संगठन क्षमता और जनसमर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। वह लगातार दक्षिण बंगाल में पार्टी को मजबूत करने और विधानसभा में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका पारिवारिक प्रभाव भी राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। उनके पिता सिसिर कुमार अधिकारी, भाई दिव्येंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी सभी भाजपा से जुड़ चुके हैं। इस प्रकार अधिकारी परिवार ने एकजुट होकर पूर्व मेदिनीपुर में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।

कुल मिलाकर, शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर एक साधारण पार्षद से लेकर संभावित मुख्यमंत्री तक का है। 2026 का चुनाव उनके कॅरियर का सबसे महत्वपूर्ण चरण साबित हो सकता है। यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी केंद्र में होंगे।

अभियान

पीपल का रहस्य: दादी-नानी की चेतावनी के पीछे छिपा विज्ञान और संस्कृति का संगम

गर्मियों की शांत रातें, खुले आकाश में टिमटिमाते तारे, दूर कहीं से आती झींगुरों की आवाज़ और गांव की चौपाल में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेना—यह दृश्य भारतीय जीवन की एक खूबसूरत झलक है। ऐसे माहौल में पेड़ों के नीचे बैठना एक प्राकृतिक सुख देता है, लेकिन जैसे ही बात पीपल के पेड़ की आती है, घर के बुजुर्ग—खासतौर पर दादी-नानी—तुरंत टोक देती हैं, "पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा।" पहली नजर में यह बात एक अंधविश्वास जैसी लगती है, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं, तो पता चलता है कि इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक समझ, पर्यावरणीय ज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान छिपा हुआ है।

भारतीय परंपरा में Peepal Tree को केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक माना गया है। इसे पवित्रता, जीवन और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस वृक्ष में Vishnu का वास होता है, और यही नहीं, Gautama Buddha ने भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस कारण पीपल को ज्ञान, मोक्ष और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गांवों में आज भी लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसे एक जीवित देवता की तरह सम्मान देते हैं।

लेकिन यही पवित्रता एक अलग तरह की सावधानी को भी जन्म देती है। लोककथाओं और मान्यताओं में यह माना गया कि शाम के बाद पीपल के पास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। यह धारणा सुनने में भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन इसके पीछे एक व्यावहारिक सोच छिपी थी। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, रोशनी के साधन सीमित थे और जंगल या खुले क्षेत्र खतरनाक हो सकते थे, तब बच्चों और महिलाओं को रात में बाहर जाने से रोकने के लिए इस तरह की कहानियों का सहारा लिया गया। "भूत पकड़ लेगा" एक डर नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच था, जिसे बुजुर्गों ने सहज भाषा में प्रस्तुत किया।

अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो भी यह चेतावनी पूरी तरह निराधार नहीं है। दिन के समय पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और ताजगी भरा रहता है। पीपल का पेड़ इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह दिन के समय अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। यही कारण है कि इसे जीवनदायी वृक्ष कहा जाता है।

लेकिन रात में स्थिति बदल जाती है। सूर्य की रोशनी के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और पेड़ श्वसन प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया सभी पौधों में होती है, लेकिन बड़े और घने पेड़ों के नीचे इसका प्रभाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रात में पीपल के नीचे बैठा रहे, तो उसे हल्की घुटन या असहजता महसूस हो सकती है, खासकर जब हवा का प्रवाह कम हो।

इसके अलावा, रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे कीट-पतंगों और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यह केवल असुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। पुराने समय में जब मच्छरजनित बीमारियों का खतरा अधिक था और उनके इलाज के साधन सीमित थे, तब ऐसे स्थानों से दूर रहने की सलाह देना एक समझदारी भरा कदम था। इस प्रकार, जो बात भूत-प्रेत की कहानी के रूप में कही गई, वह वास्तव में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी एक चेतावनी थी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीपल का पेड़ अक्सर पुराने मंदिरों, श्मशान घाटों या सुनसान स्थानों के पास पाया जाता है। इन स्थानों का वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत और रहस्यमयी होता है, जिससे लोगों के मन में भय की भावना उत्पन्न हो सकती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी "भूत-प्रेत" की अवधारणा से जोड़ दिया गया, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से इन स्थानों से दूरी बनाए रखें।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति और जीवन के बीच एक गहरा संबंध है। यहां हर पेड़, हर नदी और हर पर्वत को एक विशेष महत्व दिया गया है। पीपल का पेड़ इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे केवल पर्यावरणीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि इसके साथ जुड़ी हर बात—चाहे वह पूजा हो या सावधानी—एक गहरी सोच का परिणाम है।

दादी-नानी की कहानियां और चेतावनियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें जीवन का अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान छिपा होता था। उन्होंने कभी विज्ञान की भाषा में बात नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में विज्ञान की सच्चाई जरूर होती थी। "पीपल के नीचे मत बैठो" जैसी बातें इसी का उदाहरण हैं, जहां एक सरल वाक्य में स्वास्थ्य, सुरक्षा और संस्कृति तीनों का समावेश है।

आज के आधुनिक युग में, जब हम हर चीज़ को वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर परखते हैं, तब भी हमें यह समझना चाहिए कि परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होतीं। उनमें समय की कसौटी पर परखी हुई समझ और अनुभव का सार होता है। अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें, तो हमें उनमें छिपी सच्चाई और उपयोगिता दोनों दिखाई देंगी।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि पीपल के पेड़ से जुड़ी यह चेतावनी एक सुंदर उदाहरण है, जहां विज्ञान और संस्कृति एक साथ चलते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर परंपरा के पीछे एक कारण होता है, और हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है। जब हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें न केवल अपने अतीत की समझ मिलती है, बल्कि वर्तमान को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यही वह संतुलन है, जो हमें आधुनिकता और परंपरा के बीच बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने ज्ञान को समृद्ध और जीवन को सुरक्षित बना सकें।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-सूरत में 3.53 लाख करोड़ रुपए के 2,792 एमओयू हुए : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ उप मुख्यमंत्री का उद्योगकारों तथा निवेशकों को आश्वासन : प्रगतिशील विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपको विश्वभर के बायर्स तक पहुँचाने तथा आवश्यक व्यवस्था प्रदान करने में संपूर्ण सहायता करेगी

▶▶ वीजीआरसी का समापन, परंतु 5 मई तक आयोजित एग्जीबिशन देखने का उप मुख्यमंत्री का अनुरोध

▶▶ दक्षिण गुजरात के विभिन्न कैटेगरी में श्रेष्ठ एमएसई तथा एमएसएमई अवॉर्ड प्रदान, हस्तकला कारीगरों का सम्मान

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ सूरत वीजीआरसी से आगामी तीन वर्ष में 2.82 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा

▶▶ आदिजाति क्षेत्रों में नॉन-पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज तथा गारमेंट सेक्टर को सरकार का प्रोत्साहन, आगामी दो वर्ष में आदिजाति क्षेत्र की 25 हजार से अधिक महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा

▶▶ अब से रीजनल कॉन्फ्रेंस में उद्योगकारों की समस्याओं के स्थल पर निवारण के लिए 'ओपन डोर मीटिंग' आयोजित करेंगे, सरकार के जिम्मेदारी अधिकारी सीधा संवाद करेंगे

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा

▶▶ गुजरात देश का ग्लोबली कनेक्टेड इंजन, वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस से दक्षिण गुजरात के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी

▶▶ आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की व्याख्या गुजरात ने देश को दी, सूरत-भरूच मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देशभर में उभरे

(जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत के ऑरो विश्वविद्यालय में 1 एवं 2 मई के दौरान आयोजित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-दक्षिण गुजरात का शनिवार को समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3,53,306 लाख करोड़ रुपए के 2,792 एमओयू होने की घोषणा की।

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने समापन सत्र में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस द्वारा दक्षिण गुजरात के विकास के लिए जो नींव रखी गई है, उससे यह परिक्षेत्र आगामी समय में बड़ी आर्थिक छलांग लगाने को तैयार हुआ है। उन्होंने गुजरात की आर्थिक शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात का देश की कुल जीडीपी में 8 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 17 प्रतिशत, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 27 प्रतिशत तथा कारगो हैंडगिंल में 40 प्रतिशत हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक प्रगति ही नहीं की, अपितु अपने बूते विश्व के एक प्रतिस्पर्धी एवं कनेक्टेडेड इकोनॉमिक इंजन के रूप में खुद को स्थापित किया है।

नीति निर्धारक सकारात्मक नीतियों से कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में उद्योगपतियों तथा सरकार के बीच दूरी थी, लेकिन 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कर उद्योगपगियों के साथ संवाद एवं सहयोग की जो संस्कृति विकसित की, वह आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल बनी है। ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व में निवेश के लिए सबसे विश्वसनीय स्थान बना है।

दक्षिण गुजरात में सेक्टरल स्ट्रेंथ की भूमिका देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सूरत के डायमंड एवं टेक्सटाइल उद्योग से लेकर भरूच-दहेज-अंकलेश्वर के केमिकल तथा फर्टिलाइजर उद्योग वैश्विक हब बने हैं। अब टेक्सटाइल के साथ गारमेंटिंग उद्योग को जोड़कर विकास के नए द्वार खोले जा रहे हैं, जो स्थानीय क्षेत्र तथा राज्य सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगा।

वैश्विक अनिश्चितताओं के समय में आत्मनिर्भर बनने तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंन कहा कि आपदा को अवसर में बदलकर गुजरात जिस प्रकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गिफ्ट सिटी तथा हाईस्पीड रेल जैसे प्रोजेक्ट्स द्वारा आगे बढ़ रहा है, वह विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में आधारभूत बनेगा। उन्होंने वीजीआरसी के आयोजन के लिए राज्य सरकार को अभिनंदन दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस दक्षिण गुजरात की क्षमता को देश एवं दुनिया के समक्ष उजागर करने वाला महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनी है। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा रोजगार सृजन के लिए यह दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक सिद्ध हुई है। आगामी तीन वर्ष में एमओयू के अनुसार प्रोजेक्ट्स कार्यरत होने से दक्षिण गुजरात के 2.82 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

श्री संघवी ने गौरवपूर्वक कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की औद्योगिक शक्ति को विश्व के समक्ष रखने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का जो विचार प्रवाहित किया था, उसके फलस्वरूप राज्य की जीडीपी 1.29 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आज 27.09 लाख करोड़ रुपए तक पहुँची है। पिछले 24 वर्ष की इस दृढ़ विकास यात्रा में टीम गुजरात तथा राज्य के व्यापारी अनेक मुश्किलों के बावजूद कभी पीछे नहीं हटे हैं।

उन्होंने जोड़ा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल प्रथम पंक्ति के उद्योगपतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतिम पंक्ति में बैठे छोटे व्यापारियों के सपने साकार करने की है। राज्य सरकार इस दिशा में कार्यरत है कि वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस का सीधा लाभ छोटे उद्यमियों को मिले।

उप मुख्यमंत्री ने एक नूतन पहल करते हुए घोषणा की कि अब से रीजनल कॉन्फ्रेंस केवल नए निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान उद्योगकारों की समस्याओं के स्थल पर ही निवारण के लिए ओपन डोर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जहाँ सरकार के जिम्मेदार अधिकारी उद्योगकारों से सीधा संवाद करेंगे। उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने की नीति पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंसेंटिव क्लियरेंस की प्रक्रिया में निरंतर गति ला रही है। पूर्व में प्रतिदिन 199 आवेदन क्लियर होते थे, जो अब दुगुने हो गए हैं और आगामी समय में यह आँकड़ा 500 के पार जाएगा। इसके अलावा; डांग, तापी, वलसाड तथा नवसारी जैसे आदिजाति क्षेत्रों में नॉन-पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एवं गारमेंट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण आदिजाति क्षेत्र की 25 हजार से अधिक महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

श्री संघवी ने उद्योगकारों-निवेशकों को आश्वासन दिया कि प्रगतिशील विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपको विश्वभर के बायर्स तक पहुँचाने तथा सभी व्यवस्था प्रदान करने में संपूर्ण सहायता करेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सेक्टर्स में हुई गहन चर्चाओं तथा मंथन उद्योगकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने अनुरोध किया कि वीजीआरसी का समापन हुआ है, लेकिन 5 मई तक आयोजित एग्जीबिशन देखने के लिए अधिक से अधिक उद्यमी युवा तथा नागरिक आएँ।

गुजरात प्रदेश संगठन अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट समिट की यह यात्रा आज 2026 में टैलेंट, टेक्नोलॉजी तथा ट्रांसपरेंसी की पर्याय बनी है। गुजरात के समृद्ध एवं रचनात्मक विकास में वाइब्रेंट समिट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज ग्रोथ उत्तरोत्तर बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया की छवि गुजरात में ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में स्थापित हुई है। व्यापार-धंधे के लिए विश्वसनीय स्थल के रूप में गुजरात उभर रहा है। गुजरात में इंडस्ट्रीज फ्रेंड्ली वातावरण है, जिसके कारण निवेश के लिए गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन बना है।

इससे पूर्व प्रारंभ में उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा ने स्वागत संबोधन में रीजनल कॉन्फ्रेंस को फलदायी बताते हुए कहा कि पिछले दो दिन में स्केल एवं स्किल के समन्वय के साथ उद्यमियों को मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। दक्षिण गुजरात के उद्योगकारों तथा युवा उद्यमियों को मजबूत मंच प्रदान करने का सफल प्रयास हुआ। यहाँ बीटूबी, बीटूजी, रिवर्स पायर्स सेलर्स मीट तथा श्रृंखलाबद्ध सेमिनारों से युवा पीढ़ी को नई दिशा मिली है।

इस अवसर पर मंत्रियों तथा महानुभावों के करकमलों से विभिन्न कैटेगरी में श्रेष्ठ एमएसई तथा एमएसएमई अवॉर्ड प्रदान किए गए। इसके अलावा; हस्तकला कारीगरों का पुरस्कार के साथ सम्मान किया गया। ऑरो विश्वविद्यालय के संचालकों का आभार के साथ सम्मान किया गया।

महानुभावों ने दक्षिण गुजरात की औद्योगिक क्षमता तथा वीजीआरसी के विजन को प्रस्तुत करने वाले विशेष सोवेनियर का अनावरण किया।

समापन समारोह में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, जलापूर्ति मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, ऑरो विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री हसमुख रामा, अग्रणी लैबग्रोन उद्योगकार स्मित पटेल, व्यापार-उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, उच्चाधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

34 साल की उड़ान थमी: Spirit Airlines ने बंद किया ऑपरेशन, 17 हजार नौकरियां संकट में

वेस्ट पाम बीच। अमेरिकी विमानन क्षेत्र को बड़ा झटका देते हुए किफायती हवाई सेवाओं के लिए जानी जाने वाली Spirit Airlines ने अपने 34 साल पुराने सफर को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। चमकीले पीले विमानों और अल्ट्रा-लो-कॉस्ट मॉडल के दम पर बाजार में अलग पहचान बनाने वाली यह एयरलाइन अब इतिहास बन गई है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए बताया कि वह तत्काल प्रभाव से अपने सभी परिचालन को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रही है।

इस फैसले के साथ ही कंपनी में कार्यरत करीब 17,000 कर्मचारियों की नौकरियों पर गहरा संकट मंडराने लगा है। विमानन उद्योग में यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि Spirit Airlines ने अमेरिका में सस्ती हवाई यात्रा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्षों तक कम किराए और आक्रामक मार्केटिंग रणनीति के जरिए कंपनी ने लाखों यात्रियों को हवाई सफर का विकल्प उपलब्ध कराया।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में स्पष्ट किया है कि उसकी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और अब ग्राहक सेवा भी उपलब्ध नहीं रहेगी। यात्रियों को उनके टिकट का रिफंड दिया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था के लिए किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं अचानक प्रभावित हुई हैं, जिससे असमंजस और परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इस घटनाक्रम के पीछे आर्थिक संकट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। दरअसल, अमेरिकी सरकार से वित्तीय राहत पैकेज नहीं मिलने के बाद कंपनी के सामने परिचालन जारी रखना लगभग असंभव हो गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भी संकेत दिए थे कि सरकार की ओर से अंतिम प्रयास किया गया, लेकिन किसी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। इससे एयरलाइन के भविष्य पर पहले ही सवाल उठने लगे थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि ने एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया। विमान ईंधन की लागत में लगातार इजाफा एयरलाइनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और Spirit Airlines जैसी लो-कॉस्ट कंपनियों पर इसका असर अधिक पड़ा है, क्योंकि उनका मुनाफा मार्जिन पहले से ही सीमित होता है।

गौरतलब है कि कंपनी पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रही थी। कोविड-19 महामारी के बाद से ही यात्रियों की संख्या में गिरावट, बढ़ती लागत और भारी कर्ज के बोझ ने इसकी स्थिति को कमजोर कर दिया था। नवंबर 2024 में कंपनी ने पहली बार 'चैप्टर 11' के तहत दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया था। उस समय तक कंपनी को 2020 की शुरुआत से 2.5 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हो चुका था।

स्थिति में सुधार न होने के कारण अगस्त 2025 में Spirit Airlines को दोबारा दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन करना पड़ा। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, उस समय कंपनी पर कुल 8.1 अरब डॉलर का कर्ज था। लगातार बढ़ते कर्ज और घटती आय के कारण कंपनी के लिए अपने परिचालन को जारी रखना संभव नहीं रह गया, जिसके चलते अंततः उसे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा।

स्कूटर और ईवी से मिली रफ्तार: TVS की बिक्री में 7% उछाल, घरेलू बाजार में मजबूत पकड़

नई दिल्ली। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता TVS Motor Company ने अप्रैल माह में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कुल बिक्री में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में उसकी कुल बिक्री बढ़कर 4,73,970 इकाई तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 4,43,716 इकाई था। यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर कई वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे यह प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

कंपनी के प्रदर्शन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने निभाई है। दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 4,55,333 इकाई रही। पिछले वर्ष अप्रैल में यह संख्या 4,30,150 इकाई थी। घरेलू बाजार में कंपनी की स्थिति और भी मजबूत रही, जहां बिक्री 8 प्रतिशत बढ़कर 3,48,545 इकाई हो गई। यह संकेत देता है कि कंपनी ने भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझते हुए अपने उत्पादों और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से अनुकूलित किया है।

हालांकि, मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी को हल्की गिरावट का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2026 में मोटरसाइकिल बिक्री घटकर 2,00,039 इकाई रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 2,20,347 इकाई थी। इस गिरावट को बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव और स्कूटर व इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर झुकाव के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, स्कूटर सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। इस श्रेणी में 24 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जिससे बिक्री 2,11,158 इकाई तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 1,69,741 इकाई थी। यह वृद्धि शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, जहां सुविधा, माइलेज और कम रखरखाव जैसे कारक ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भी कंपनी ने तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। अप्रैल माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 36 प्रतिशत बढ़कर 37,771 इकाई तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 27,684 इकाई थी। यह उछाल न केवल कंपनी की रणनीतिक दिशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने भी इस बदलाव को गति दी है।

तीन-पहिया वाहनों के सेगमेंट में भी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बिक्री 18,637 इकाई तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 13,566 इकाई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से शहरी परिवहन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के कारण देखी जा रही है, जहां तीन-पहिया वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कंपनी की उपस्थिति स्थिर बनी हुई है। कुल निर्यात 3 प्रतिशत बढ़कर 1,20,008 इकाई तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 1,16,700 इकाई था। TVS Motor Company का वैश्विक नेटवर्क मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है, जहां कंपनी लगातार अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टीवीएस की यह वृद्धि उसकी विविध उत्पाद श्रृंखला और बदलते बाजार रुझानों के अनुरूप रणनीति का परिणाम है। जहां एक ओर कंपनी पारंपरिक पेट्रोल वाहनों में अपनी पकड़ बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी तेजी से निवेश कर रही है। यह संतुलन भविष्य की प्रतिस्पर्धा में कंपनी को बढ़त दिला सकता है।

कुल मिलाकर, अप्रैल माह का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि टीवीएस मोटर कंपनी ने बाजार की चुनौतियों के बावजूद अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। स्कूटर और ईवी सेगमेंट में तेजी से बढ़ती मांग ने कंपनी को नई ऊर्जा दी है, जबकि मोटरसाइकिल सेगमेंट में सुधार की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी अपनी इस गति को कैसे बनाए रखती है और बदलते ऑटोमोबाइल परिदृश्य में खुद को किस तरह आगे बढ़ाती है।

राजस्थान में 'शर्ट बदलकर गिरफ्तारी' विवाद: विधायक-इंजीनियर टकराव ने पकड़ा तूल, दोनों पक्षों के आरोपों से गरमाई सियासत

श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक कथित मारपीट और गिरफ्तारी का मामला अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन गया है। Jaideep Bihani और राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (RUIDP) के सहायक अभियंता Jaganlal Bairwa के बीच हुए टकराव को लेकर दोनों पक्षों के दावे एक-दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। घटना के बाद इंजीनियर संगठनों के विरोध-प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाज़ी और जांच की मांगों ने इस प्रकरण को और अधिक गंभीर बना दिया है।

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा ने आरोप लगाया कि उन्हें विधायक सेवा केंद्र पर बैठक के लिए बुलाया गया था। उनके अनुसार, जैसे ही वे अपने दो कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे, विधायक जयदीप बिहाणी ने उन पर नाराजगी जताई और कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बैरवा का कहना है कि इसके बाद विधायक के 20–25 समर्थक भी उन पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मारपीट के दौरान उनकी शर्ट खून से सनी हुई थी, जिसे छिपाने के लिए उन्हें बाजार से नई शर्ट मंगवाकर पहनाई गई और फिर पुलिस को बुलाकर उन्हें ही गिरफ्तार करवा दिया गया।

जेल से रिहा होने के बाद बैरवा ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उनके साथ न केवल शारीरिक हिंसा हुई, बल्कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश भी की गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और आंख के पास सूजन को उन्होंने अपने आरोपों का सबूत बताया। बैरवा ने विधायक द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया।

दूसरी ओर, विधायक Jaideep Bihani ने पूरी तरह अलग कहानी पेश की है। उनका कहना है कि शहर में कुछ दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित थी और इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसी सिलसिले में बैरवा को जवाब देने के लिए बुलाया गया था। विधायक का आरोप है कि बैरवा काफी देर से पहुंचे और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने गुस्से में आकर विधायक को थप्पड़ मार दिया, जिससे उनका चश्मा टूट गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाकर बैरवा और उनके साथ आए कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सच क्या है। यदि विधायक के अनुसार इंजीनियर ने मारपीट की, तो चोटें इंजीनियर के शरीर पर कैसे आईं? वहीं, यदि इंजीनियर के आरोप सही हैं, तो फिर उन्हें ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार क्यों किया गया? घटना के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बैरवा के शरीर पर चोटों के निशान और फटी शर्ट दिखाई देने की बात भी चर्चा में है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

इसी बीच राजस्थान के इंजीनियर संगठनों ने इस घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। हनुमानगढ़ सहित कई जगहों पर इंजीनियरों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की हिंसा की जाती है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है और इससे सरकारी कर्मचारियों में भय का माहौल बन सकता है।

विधायक पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि बिना निष्पक्ष जांच के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक पर लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रेरित हो सकते हैं।

इस घटना ने प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर निशाना साधा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच टकराव के मामले सामने आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, पूर्व में कांग्रेस विधायक Giriraj Malinga पर भी एक इंजीनियर के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद व्यापक विवाद हुआ था और अंततः कार्रवाई करनी पड़ी थी। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करती है।

फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग तेज हो गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन-प्रशासन के संबंधों, कानून के राज और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों से जुड़े बड़े सवाल भी खड़ा करता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का निष्कर्ष क्या निकलता है और क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।

स्कूल के पानी से हड़कंप : बाड़मेर में 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, शरीर पर लाल चकत्ते उभरे, जांच तेज

बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पानी पीने के कुछ ही मिनटों बाद एक-एक कर 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों के शरीर पर अचानक लाल धब्बे और तेज खुजली जैसे लक्षण दिखाई दिए, जिससे स्कूल परिसर में दहशत फैल गई। यह घटना Barmer जिले के सनावड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (मेघवालों की बस्ती) की है, जहां उस दिन 'नो बैग डे' के तहत गतिविधियां चल रही थीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेस्ट टाइम के दौरान बच्चों ने स्कूल परिसर में उपलब्ध पानी पिया था। इसके कुछ ही देर बाद कई बच्चों ने खुजली, जलन और त्वचा पर लाल चकत्तों की शिकायत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते करीब 13 छात्र प्रभावित हो गए। अचानक बिगड़ती स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। लेकिन बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया।

सबसे पहले सभी बच्चों को सनावड़ा के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया। हालांकि, कुछ बच्चों की स्थिति को गंभीर मानते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए Barmer District Hospital रेफर कर दिया गया। 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया।

घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक भी अस्पताल पहुंचने लगे। अपने बच्चों की हालत देखकर कई माता-पिता घबरा गए और प्रशासन से जवाब मांगने लगे। अस्पताल परिसर में चिंता और बेचैनी का माहौल देखने को मिला, हालांकि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज शुरू कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर Rajendra Singh Chadawat ने बताया कि बच्चों में एलर्जी जैसे लक्षण पाए गए हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर पानी में ऐसा क्या था, जिससे बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

प्राथमिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि या रासायनिक तत्व मिल जाने के कारण यह घटना हुई हो सकती है। हालांकि, अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, खासकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने या पाइपलाइन में गड़बड़ी के कारण इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि बच्चों की सेहत से कोई समझौता न हो।

स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है।

फिलहाल, प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल परिसर में पानी की आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही है।

यह घटना केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएगी।

गुजरात गौरव दिवस 2026 का राज्य स्तरीय उत्सव – सूरत

सूरत के डूमस सी-फेस में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'गौरववंती गुजरात, विरासतथी विकास' आयोजित हुआ

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत शहर-जिले के विकास कार्यों के लिए 7.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया
- मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी तथा मनपा आयुक्त को कुल 7.50 करोड़ रुपए के चेक अर्पित किए

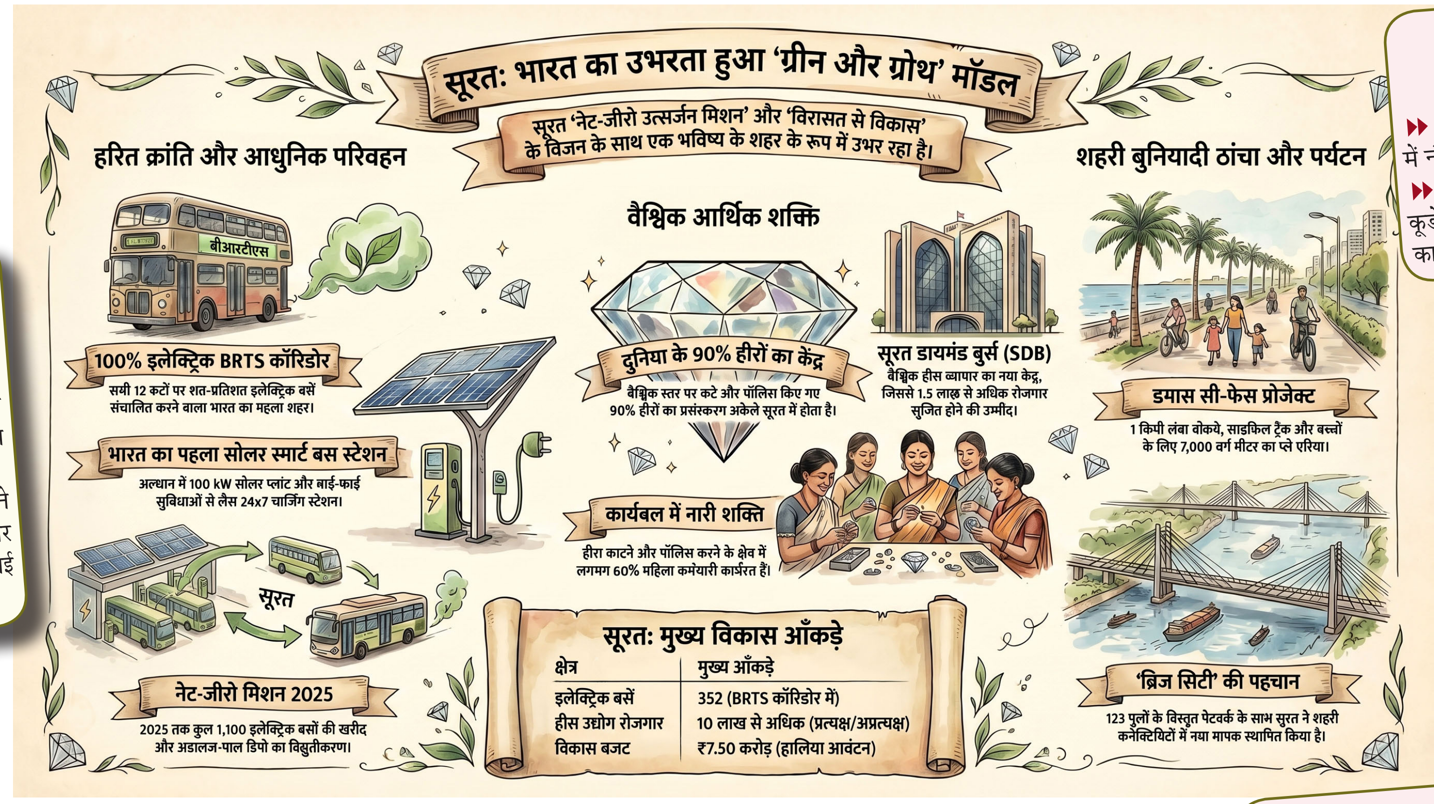

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- सूरत अब इंडस्ट्रियल सिटी के साथ ग्रीन, क्लाइमेट रेजीलियेंट तथा फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में उभरा है
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में गुजरात देश का 'ग्रोथ इंजन' तथा विकास का 'रोल मॉडल' बना
- ग्रीन ग्रोथ के पर्याय के रूप में सूरत ने 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें तथा 'सर्कुलर वाटर इकोनॉमी' मॉडल अपना कर देश को नई दिशा दिखाई है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

- 'टीम गुजरात' के रूप में राज्य को हर क्षेत्र में नंबर बनाने के लिए नागरिक सहयोगी बनें
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंके तथा कूड़ेदान का उपयोग कर स्वच्छता कर्मचारियों का बोझ घटाएँ

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी

- शून्य से सृजन कर गुजरात आज देश का अग्रणी राज्य बना है
- सूरतियों ने केवल सूरत का स्वरूप ही नहीं बदला, बल्कि वे विश्व में जहाँ भी बसते हैं, वहाँ की सूरत बदलने की क्षमता रखते हैं

(जीएनएस)। गांधीनगर : 1 मई को गुजरात गौरव दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह अंतर्गत सूरत के डूमस सी-फेस में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी की अध्यक्षता में तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी एवं महानुभावों की उपस्थिति में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'गौरववंती गुजरात, विरासतथी विकास' आयोजित हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल, वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, जलापूर्ति मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानशेरिया, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेशभाई मोदी, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल तथा विधायकगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने गुजरात की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि दशकों पहले जो राज्य पानी तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता था, वह आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व एवं गुजरातियों के परिश्रम से देश का नंबर वन राज्य बना है। राज्यपाल ने अतीत के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि बृहन्मुंबई से अलग होने के बाद गुजरात में पीने के पानी की विकट समस्या थी। एक समय प्रशासन का मुख्य काम ट्रेन द्वारा आने वाले पानी का वितरण करना तथा संघर्ष टालना था। रेगिस्तान, पहाड़ों तथा समुद्र तट वाले इस प्रदेश में उद्योगों, सड़कों या बिजली जैसी ढाँचागत सुविधाओं का अभाव था, परंतु गुजरातियों के अथक परिश्रम एवं श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिन-रात कार्य करके जो नई जनहितकारी नीतियाँ लागू कीं, उनके कारण आज गुजरात की कायापलट हुई है।

उन्होंने जोड़ा कि आज गुजरात सेमीकंडक्टर तथा वडोदरा में विमान निर्माण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी अग्रसर है। सूरत के योगदान की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सूरतियों ने केवल सूरत का ही स्वरूप नहीं बदला, बल्कि वे विश्व में जहाँ भी बसते हैं, वहाँ की सूरत बदलने की क्षमता रखते हैं।

उन्होंने कहा कि सूरत का डायमंड तथा टेक्सटाइल उद्योग आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन गया है। उन्होंने गुजरात के नागरिकों का भारतीय जीवन मूल्यों, अध्यात्म एवं भौतिक उन्नति के संगम के साथ राज्य को और ऊँचाई पर ले जाने तथा परिश्रम के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्र निर्माण में तन-मन से जुड़ जाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 1 मई, 1960 को बृहन्मुंबई से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए गुजरात के पास शुरुआत में ढाँचागत सुविधाओं का अभाव था, परंतु परिश्रमी गुजरातियों की क्षमता, कौशल एवं सूझ-बूझ के कारण गुजरात प्रगति के पर्याय समान बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में गुजरात आज देश का 'ग्रोथ इंजन' तथा विकास का वैश्विक 'रोल मॉडल' बना है। वर्ष 2001 में श्री नरेन्द्र मोदी के शासनधुरा संभालने के बाद गुजरात की विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पर्वों का उत्सव जिला मुख्यालयों पर मनाने की जो परंपरा शुरू की है, उससे लोक शक्ति विकास के साथ जुड़ी है और जन-जन में राष्ट्र हित का भाव जागा है तथा लोग शासन में सहभागिता का अनुभव कर रहे हैं। सूरत की विकास यात्रा की प्रशंसा करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सूरत की आज हीरा तथा टेक्सटाइल उद्योग के कारण विश्वभर में गौरवशाली ख्याति है। हजीरा की मल्टीनेशनल कंपनियों, डायमंड बोर्स तथा जेम्स-ज्वैलरी पार्क ने सूरत की कायापलट की है। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने के साथ 123 पुलों की श्रृंखला द्वारा 'सिटी ऑफ ब्रिजेस' की विशिष्ट पहचान प्राप्त की है।

सूरत के आँगन में 66वें राज्य स्तरीय 'गुजरात गौरव दिवस' समारोह के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के पर्याय के रूप में सूरत ने 100 प्रतिशत बसें तथा 'सर्कुलर वाटर इकोनॉमी' मॉडल अपना कर देश को नई दिशाई दिखाई है। प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को साकार करने में आवश्यक 'विकसित गुजरात' के लिए सूरत तथा सूरतवासी अग्रसर रहेंगे।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने राज्य के नागरिकों को गुजरात गौरव दिवस का अभिनंदन देते हुए कहा कि प्रत्येक गुजराती के अथक परिश्रम एवं संघर्ष के परिणामस्वरूप आज गुजरात देश का अग्रणी राज्य बना है। राज्य सरकार तथा जनता 'टीम गुजरात' के रूप में कार्य कर रही है, जिसके कारण विकास की गति बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रही है। श्री संघवी ने स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए कहा कि गुजरात के शहर आज स्वच्छता में देशभर में शीर्ष पर हैं, तब यह गौरव बनाए रखने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फेंकने तथा कूड़ेदान का उपयोग कर स्वच्छता कर्मचारियों का बोझ घटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्मित सार्वजनिक संपत्तियों तथा पर्यटन स्थलों का रखरखाव प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने डूमस के समुद्र तट पर की गई अत्याधुनिक सुविधाओं को वर्षों तक अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्पबद्ध होने का बलपूर्वक अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात को सभी दिशाओं में नंबर वन बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना अनिवार्य है। उन्होंने दैनिक जीवन में तेल एवं चीन का उपयोग सीमित कर उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने स्थानीय निकाय तथा पंचायत चुनावों में जनता द्वारा दिए गए अपार प्रेम तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की टीम जन भागीदारी के साथ गुजरात को विकास के नए शिखरों पर ले जाएगी।

इस अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के करकमलों से राज्य के व्यक्ति विशेषों को 'गुजरात गरिमा अवॉर्ड' प्रदान किए गए। जिले के गौरव में वृद्धि करने वाले महानुभावों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ सूरत जिले की विकास यात्रा को दर्शाने वाली दो पुस्तकों 'विकास वाटिका' तथा 'कॉफी टेबल' बुक का अनावरण भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने सूरत शहर-जिले के विकास कार्यों के लिए 7.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी को 2.50 करोड़ रुपए, शहरी विकास के लिए मनपा आयुक्त डॉ. एम. नागराज को 2.50 करोड़ रुपए तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिला विकास अधिकारी श्रीमती शालिनी गोयल को 2.50 करोड़ रुपए के चेक अर्पित किए गए।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के करकमलों से गुजरात गरिमा अवॉर्ड प्रदान किए गए

गुजरात गौरव दिवस समारोह अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले एवं राज्य का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभाशाली विशिष्ट व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के करकमलों से गुजरात गरिमा अवॉर्ड प्रदान किए गए। इनमें कला क्षेत्र में श्री भरत कांतिलाल सालवी, समाज सेवा के लिए श्री हसमुखभाई दवे, चिकित्सा सेवा के लिए डॉ. धवल नायक, खेल-कूद के लिए सुश्री बकुलाबेन पटेल, खेल-कूद एवं कला क्षेत्र के लिए सुश्री हेत्वी खिमसुरिया शामिल हैं। इसके अलावा सूरत जिले के प्रतिष्ठित महानुभाव पद्मश्री सर्वश्री सवजीभाई धोळकिया, नीलेशभाई मांडलेवाला, डॉ. कनुभाई टेलर, यजदी करंजिया, मथुरभाई सवाणी तथा अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव निरंजनाबेन कलार्थी, मोहम्मद वानिया, मानव ठक्कर तथा हरमित देसाई के परिजनों को सम्मानित किया गया।

गुजरात स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए डूमस सी-फेस में गौरववंती गुजरात, विरासतथी विकास थीम के साथ भव्य रंगारंग मल्टीमीडिया कार्यक्रम से सूरतवासी मंत्रमुग्ध

डूमस सी-फेस में गुजरात स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए गौरववंती गुजरात, विरासतथी विकास थीम के साथ आयोजित मल्टी-मीडिया रंगारंग कार्यक्रम निहार कर सूरतवासी मंत्रमुग्ध हुए। 50 मिनिट की इस भव्य सांस्कृतिक मेगा इवेंट में राज्य की कला एवं संस्कृति की झाँकी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक कलाकारों ने अतीत से लेकर वर्तमान विकास तक की यात्रा को नाटक के रूप में भव्य लाइट एंड साउंड के समन्वय के साथ प्रस्तुत किया।

सूरत में 66वां गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया, स्वच्छता कर्मचारियों की उपस्थिति ने इस उत्सव की शोभा और बढ़ा दी

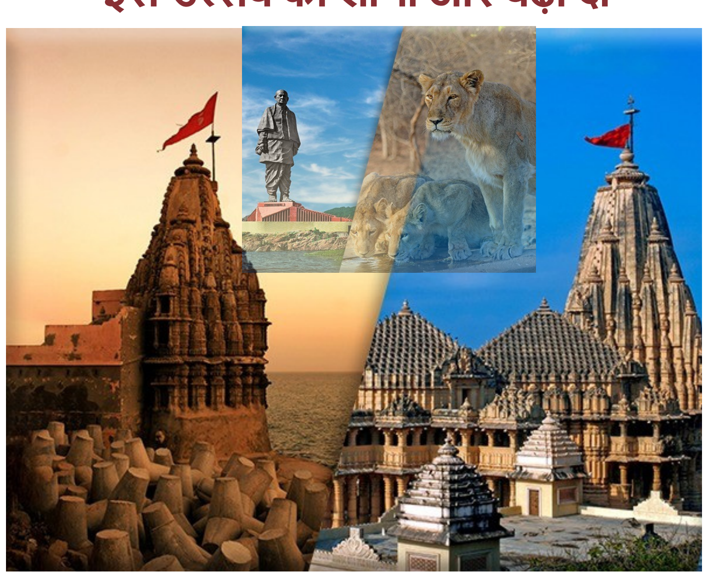

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का विभाजन महागुजरात आंदोलन द्वारा हुआ था। महागुजरात आंदोलन में, नेता इंदुलाल याग्निक गुजरात और महाराष्ट्र के विभाजन के लिए आंदोलन चला रहे थे। और उन्हें 1 मई 1960 को इसमें सफलता मिली। राज्य का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में परमपूज रवि शंकर महाराज के संरक्षण में आयोजित किया गया था। डॉ. जीवराज मेहता ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उनके बाद से लेकर आज तक सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है।

पहली बार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में सूरत नगर परिसर के प्रांगण में वाई-जंक्शन सूरत में सफाईकर्मियों की उपस्थिति में 66वां गुजरात गौरव दिवस मनाया गया। यह पूरे गुजरात के लिए खुशी और गर्व का विषय है। सफाईकर्मियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और सभी सफाईकर्मी बधाई के पात्र हैं। सफाईकर्मियों की उपस्थिति में गुजरात राज्य के गौरवशाली स्थापना दिवस को मनाकर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों को गौरवान्वित किया है। सूरत नगर परिसर में आयोजित इस गौरवशाली दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ सफाईकर्मियों को गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, राज्य उपाध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा, महासचिव सैयदभाई शेख, कार्यकारी अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, महासचिव श्यामभाई तेनिया, महासचिव रविभाई सुरती आदि ने बधाई दी।

भ्रामक ऑफर पर कंज्यूमर कोर्ट की सख्ती: सूरत में रिज़ॉर्ट कंपनी को रकम लौटाने का आदेश

(जीएनएस)। सूरत। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सूरत के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन ने एक निजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ग्राहकों को आकर्षक वादों और भ्रामक जानकारी के जरिए लुभाना और बाद में उन वादों को पूरा न करना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानून के तहत दंडनीय भी है। इस मामले में शिकायतकर्ता जीनल पटेल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आयोग ने ब्यू माउंटेन रिज़ॉर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी को रकम वापस करने और मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार, जीनल पटेल ने 31 मार्च 2024 को कंपनी की एक मेंबरशिप योजना में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्होंने 67,000 का भुगतान किया। कंपनी द्वारा आयोजित एक सेमिनार में उन्हें कई आकर्षक सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था, जिनमें फाइव-स्टार होटलों से जुड़ाव, विशेष छूट और प्रीमियम सेवाओं की उपलब्धता जैसे दावे शामिल थे। इन दावों से प्रभावित होकर उन्होंने मेंबरशिप ले ली, लेकिन बाद में जब उन्होंने सेवाओं का लाभ उठाने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि कई वादे वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

शिकायत में यह भी कहा गया कि कंपनी ने जिन होटलों और सुविधाओं का उल्लेख किया था, उनमें से कई सूची में शामिल ही नहीं थे या उनकी उपलब्धता सीमित थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भ्रामक जानकारी का सहारा लिया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने उनकी मेंबरशिप को आगे बेचने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा, ईएमआई पर ब्याज काटे जाने के बावजूद पूरी राशि वापस नहीं की गई, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया।

इस पूरे मामले के दौरान कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया,

जिसके चलते आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाया। पीठ में शामिल चीफ जस्टिस R. L. Thakkar और सदस्य Purvi Joshi ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने स्पष्ट रूप से गलत व्यापारिक प्रथाओं का पालन किया है और ग्राहक को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त किया है।

आयोग ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 70,000 की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए। यह ब्याज 23 अगस्त 2024 से भुगतान की तिथि तक लागू होगा। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 3,000 का मुआवजा तथा 2,000 केस खर्च के रूप में देने का भी आदेश दिया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी राशि 30 दिनों के भीतर अदा की जानी चाहिए, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Preeti Jignesh Joshi और Bela Girnara ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिसके आधार पर आयोग ने यह फैसला सुनाया। उनके तर्कों में यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए जानबूझकर भ्रामक जानकारी दी और बाद में अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की।

यह फैसला न केवल जीनल पटेल के लिए न्याय की जीत है, बल्कि उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है, जो अक्सर ऐसे आकर्षक ऑफरों के जाल में फंस जाते हैं। आज के समय में जब मार्केटिंग के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही, यह फैसला यह भी दर्शाता है कि यदि कोई कंपनी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का सहारा लेती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को और मजबूत बनाते हैं और कंपनियों को यह संदेश देते हैं कि पारदर्शिता और ईमानदारी ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। सूरत कंज्यूमर कोर्ट का यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा, जहां ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है।

अंततः, यह मामला यह साबित करता है कि उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, तो न्याय प्राप्त करना संभव है। अदालत का यह सख्त रुख न केवल दोषी कंपनियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता के लिए एक भरोसा भी है कि कानून उनके साथ खड़ा है।

प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए, भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 157वें स्थान पर है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। 30 अप्रैल को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है। 2025 में भारत 151वें स्थान पर था, यानी छह पायदान नीचे। पत्रकारिता निगरानी संस्था रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) ने कहा कि उसके सूचकांक में शामिल सभी 180 देशों और क्षेत्रों का औसत स्कोर पिछले 25 वर्षों में इतना कम कभी नहीं रहा। सूचकांक के इतिहास में पहली बार, दुनिया के आधे से अधिक देश अब प्रेस स्वतंत्रता की "गंभीर" या "अत्यंत गंभीर" श्रेणी में आते हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन सूचकांक में शीर्ष पर हैं। सऊदी अरब, ईरान,

चीन, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया सबसे नीचे हैं। आरएसएफ (रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स) के अनुसार, विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया के कई हिस्सों में पत्रकारिता की स्थिति में चिंताजनक गिरावट आई है। कुछ स्थानों पर सीमित सुधार के बावजूद, 180 में से 100 देशों में प्रेस स्वतंत्रता स्कोर में गिरावट आई है। वैधता सूचकांक में पिछले वर्ष सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि दुनिया भर में पत्रकारिता को तेजी से अपराध के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका में भी स्थिति नकारात्मक रूप से बदल गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका सात पायदान नीचे खिसक गया है। और कई लैटिन अमेरिकी देश हिंसा और दमन के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं।

आरएसएफ ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहाः पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया स्वामित्व का बढ़ता केंद्रीकरण और मीडिया संगठनों का विशिष्ट राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति बढ़ता पूर्वाग्रह, इन सभी कारकों ने "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र" में प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है। 2014 से देश में प्रधानमंत्री मोदी का शासन है, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतीक हैं। सरकारों ने मीडिया को दबाने के लिए राजद्रोह, मानहानि और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से संबंधित औपनिवेशिक काल के कानूनों का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं किया है। और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल भी पत्रकारों के खिलाफ तेजी से किया जा रहा है।

गर्मी में राहत : वटवा–मुंबई सेंट्रल के बीच एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू

(जीएनएस)। वडोदरा। ग्रीष्मकालीन सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए Western Railway ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वटवा और Mumbai Central railway station के बीच एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन विशेष किराए पर संचालित होगी और सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन संख्या 09082 वटवा–मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार रात 22:40 बजे वटवा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह सेवा 08 मई 2026 से 26 जून 2026 तक चलेगी। वहीं वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 09081 मुंबई सेंट्रल–वटवा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार रात 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 07:20 बजे वटवा पहुंचेगी। यह सेवा 07 मई 2026 से 25 जून 2026 तक संचालित की जाएगी।

इस विशेष ट्रेन का मार्ग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन Vadodara, Surat, Vapi और Borivali जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इन स्टॉपेज के कारण न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि बीच के शहरों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी यह ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प बनेगी।

कोच संरचना की बात करें तो इस ट्रेन में एसी 3-टियर कोच उपलब्ध रहेंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। गर्मी के मौसम में एसी कोच की मांग काफी बढ़ जाती है, ऐसे में यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

टिकट बुकिंग को लेकर भी रेलवे ने स्पष्ट जानकारी दी है। ट्रेन संख्या 09081 और 09082 के लिए आरक्षण 03 मई 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC Rail Connect (आईआरसीटीसी वेबसाइट/ऐप) के माध्यम से शुरू हो जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय, ठहराव और अन्य विवरणों की पुष्टि रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि यह विशेष सेवा न केवल यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी, बल्कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होगी। हर साल गर्मियों में गुजरात और मुंबई के बीच यात्रा करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि होती है, ऐसे में इस तरह की अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन बेहद आवश्यक हो जाता है। कुल मिलाकर, वटवा–मुंबई सेंट्रल एसी सुपफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। बेहतर समय, सुविधाजनक स्टॉपेज और एसी कोच की उपलब्धता इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है और क्या रेलवे भविष्य में इस तरह की और सेवाएं शुरू करता है।

पालीताना रेलवे स्टेशन पर सतर्कता व ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण, यात्री का खोया मोबाइल सुरक्षित लौटाया गया

(जीएनएस)। दिनांक 02 मई, 2026 (शनिवार) को प्रातः लगभग 10:00 बजे पालीताना रेलवे स्टेशन पर तत्काल बुकिंग हेतु एक यात्री काउंटर पर आए। बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात वे अनजाने में अपना मोबाइल फोन काउंटर पर ही छोड़कर चले गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क श्री जयवीर सिंह जडेजा की सतर्क दृष्टि जब मोबाइल पर पड़ी, तो उन्होंने तत्काल जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इसकी सूचना ऑन ड्यूटी डिप्टी स्टेशन अधीक्षक (SS) को दी तथा मोबाइल को सुरक्षित अपने संरक्षण में रखा।

कुछ समय पश्चात संबंधित यात्री वापस स्टेशन पर पहुंचे और अपना मोबाइल छूट जाने की जानकारी दी। रेलवे स्टाफ द्वारा पूरी सावधानी बरतते हुए यात्री की पहचान का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें उनके मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का मिलान किया गया।

सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत बुकिंग क्लर्क श्री जयवीर सिंह जडेजा एवं ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर श्री श्रीकांत कुमार द्वारा यात्री को उनका मोबाइल सुरक्षित रूप से सुपुर्द कर दिया गया।

इस घटना ने एक बार फिर भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की ईमानदारी, सतर्कता एवं यात्री सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया है। भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने मंडल के कर्मचारियों के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की तथा यात्रियों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।